RAJYA SABHA

Friday the 11th, *August,* 1989/20 *Sravana,* 1911 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock.

Mr. Chairman in the Chair

ORAL ANSWERS JO

QUESTIONS

Entitlement for allotment of Government accommodation from the Central Pool

361. DR. NARREDDY THULASI REDDY : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of the organisations which though technically not termed as Central Government Departments, are entitled for the allotment of accommodation from the Central Pool; and

(b) the reasons for which Kendriya Vidyalaya Sangathan employees are not entitled for this facility?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI) : (a) and (b) Only Central Government Departments and Organisations declared eligible under Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963 are entitled to get allotment of accommodation from general pool. Since Kendriya Vidyalaya Sangathan is an autonomous organisation, its employees are not eligible for allotment of general pool accommodation.

DR. NARREDDY THULASI REDDY : Sir, the hon. Minister has said that only Central Governmeat departments and organisations declared eligible under the Allotment of Government Residences Rules, 1963, are entitled to get allotment from the general pool. I would like to know when and how an organisation is declared eligible under the Allotment of Government Residences Rules, 1963. I would also like to know whether the Council of Scientific and Industrial Research and the three Akademies of National School of Drama have been declared eligible for this purpose. Though autonomous technically, the Kendriya Vidyalaya Sangathan is "State" within the meaning of article 12 of the Constitution. Moreover the Kendriya Vidyalaya Sangathan is catering to the educational needs of the children of Central Government employees. So, what is the objection in bringing the Kendriya Vidyalaya Sangathan under these Rules?

श्रीमती मोहसिना किदवई : सभापति जी, जितने ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के इम्प्लायीज हैं जो इलीजिबल हैं जिनको एकोमोडेशन दिया जाता है उनकी लिस्ट मेरे पास है । वह बहुत लम्बी है । अगर आप चाहें तो मैं सदन की टेबुल पर रख दूं ।

जहां तक केन्द्रीय विद्यालयों का सवाल है, यह बात सही है कि वहां गवर्नमट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं। माननीय सदस्य यहां उनका प्रश्न उठा रहे हैं जबकि केन्द्रीय विद्यालय संस्थान ने अभी तक हमें एप्रोच नहीं किया कि हम उनको भी गवर्नमेंट एकोमोडेशन दें क्योंकि उनके अपने एकोमोडेशन उनके जो स्कूल्स हैं उन्हीं के करीब होते हैं । अगर उन्हें जरूरत हो जमीन की और वे बनाना चाहें जैसे नोएडा में एक एकड़ जमीन ली है और वहां बना रहे हैं, फरीदाबाद में ले रहे हैं, तो कर सकते हैं लेकिन उन्होंने अब तक हमें एप्रोच नहीं किया है शायद यह सोचकर कि यह संगठन इलीजिबल जोन में नहीं आता है । इसलिए उन्होंने कभी एप्लाई नहीं किया। मुझे मालूम नहीं कि किस बिना पर सदस्य यहां पर सवाल कर रहे हैं । आज तक उनकी कोई भी एप्लीकेशन नहीं आई है कि हमें दिया जाये ।

DR. NARREDDY THULASI REDDY ; Sir, is it not a fact that

the all India Kendriya Vidyalaya Sangathan Association has been pressing the demand of entitlement of KVS teachers for allotment from the General pool since 1982?

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: Sir, I have said that they have, never applied to our department for being given this general pool accommodation.

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA : Mr. Chairman, Sir, I think the hon. Minister is aware of the great difficulties the Government servants are facing with regard to accommodation. I would like to know from the hon. Minister whether in view of the great need and pressure on her department for providing accommodation, she has some plan for augmenting the number of houses that are available. After all, this should not be a chronic problem for the New Delhi constituency as over 60,000 Government employees are here and they all need accommodation. The people are pressing for more accommodation. I would like to know from the hon. Minister if she has any schemes and what is the number of people actually waiting for being accommodated in these houses?

MR. CHAIRMAN : Mr. Gupta, the question is about organisations. It is not about Government employees. If you read the question, you will see that your supplementary does not arise.

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA : Mr. Chairman, Sir, I accept. . .

MR. CHAIRMAN : You cannot ask everything. The question is limited to orgnisations. It is not about Government employees. You can put a separate question on this. As I said, this question is only about organisations.

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA : Sir, the Government employees' association.. MR. CHAIRMAN : No.

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA 5 The hon. Minister is willing to answer.

MR. CHAIRMAN : She may be ready to answer but there are rules of the House.

•SHRI M. A. BABY : Sir, with your permission, if I may be allowed to ask....

MR. CHAIRMAN : You can ask only about organisations, not about Government employees.

SHRI M. A. BABY : From the Urban Development Ministry, the organisation has requested for allotment.

MR. CHAIRMAN : Which organisation?

SHRI M. A. BABY : Similarly, there is a pool, eminent artistes pool. Our hon. Member, Pt. Ravi Shankar, is here. He lias also taken up the issue with Mohsina Kidwaiji regarding an outstanding artiste, Shri Appunni Kartha, who falls in the category of eminent artistes. The Secretary of the Department of Culture, Shrimati Kapila Vatsay an, has also written to the hon. Minister.

MR. CHAIRMAN : It is an individual question. If she knows...

SHRI M. A. BABY : He falls in the category of eminent artistes.: I would request the hon. Minister to sympathetically consider this, case.

MR. CHAIRMAN : If the hon. Minister knows, she can answer, or, she can inform you later.

श्रीमती मोहसिना किदवई : अध्यक्ष जी, इस में मुख्तलिफ कोटे हैं, जैसे वैलफेयर मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री आफ कल्चर का है और उसमें एमिनेंट आर्टिस्ट्स आते हैं । इसमें हमारा कोटा है । उस कोटे में जितने रेकोमेंडेशंस वहां से आते हैं, उनमें से जितने अकोमोडेट कर पाते हैं, करते हैं । यह एक इंडिविजुअल केस है, मैं देखूंगी कि इसके बारे में क्या हुआ है ।

DR. NAGEN SAIKIA : Mr. Chairman, Sir, hundreds of K.V.S. teachers are without any housing facility. Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether some new scheme would be taken up for providing accommodation to the K.V.S. teachers in the major cities of the country.

श्रीमती मोहसिना किदवई : अध्यक्ष जी, जहां तक मुझे मालूम है, जो केंद्रीय विद्यालय संस्थान है, अभी इन्होंने एक एकड़ जमीन नोएडा में ली है, जहां यह 48 क्वार्टर्ज बना रहे हैं । सब मिला कर जो हमारे पास इनफार्मेशन है, उसके अनुसार पूरी कंट्री में 732 केंद्रीय विद्यालय हैं । उनमें से 109 केंद्रीय विद्यालयों में स्टाफ क्वार्टर्ज अभी तक बन चुके हैं, बाकी जमीन की व्यवस्था कर रहे हैं । वह खुद उसकी कोशिश करते हैं । अभी उन्होंने एक एकड़ जमीन नोएडा में ली है और पांच एकड़ फरीदाबाद में हरियाणा गवर्नमेंट से वह मांग रहे हैं ।

इसलिए अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क उन्होंने शुरू किया है । यह 48 क्वार्टर्ज तो सी०पी० डब्ल्यू० डी० बना रहा है । इसलिए मुझ मालूम है, और वह कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहां विद्यालय होते हैं, उसके करीब ही वह चाहते हैं कि उनके घर हों ।

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Mr. Chairman, Sir, I would like to know from the hon. Minister as to what steps "have been taken to meet the long-pending demand **of the staff of both the Secretariats of Parliament in regard to accommodation.**

श्रीमती मोहसिना किदवई : अध्यक्ष जी, माननीय मेम्बरान जो पूछ रहे हैं, बिलकुल सही है कि इस वक्त सेंट्रल पूल में डिमांड बहुत है और उतने मकानात हमारे पास देने के लिए नहीं हैं । मुख्तलिफ पूल्स है, डिफेंस मिनिस्ट्री का, टेली-कम्यूनिकेशंस का—उन सबको हमने ... (व्यवधान)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : I am not asking about Members of Parliament. I am asking about staff of Parliament.

श्री सभापति : यह तो सिर्फ मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट, और यहां के स्टाफ के बारे में पूछ रहे हैं ।

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI : I am not answering about Members of Parliament...

MR. CHAIRMAN : You are satisfied जिनको मिल गये हैं । मुझे तो खबर मिली है कि अभी नहीं मिले हैं । बहुत से बेचारे परेशान हैं । नागालैंड के मेम्बर अपने नागालैंड हाऊस में ठहरे हुए हैं । आपने उनको जगह नहीं दी है । यह मध्य प्रदेश के मेम्बर भी शिकायत कर रहे हैं । ... (व्यवधान)

श्रीमती मोहसिना किदवई : लोक सभा और राज्य सभा का जो इम्पलायीज का पूल है, वह पूल अलग है और जनरल पूल से हमने अलग दे रखे हैं । ... (व्यवधान)

श्री सभापति : इनको भी नहीं मिला है ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : एक दर्जन के आसपास है, जिनको मकान नहीं मिला है ।

श्रीमती मोहसिना किदवई : लेकिन उसमें लोक सभा हाऊस कमेटी है और राज्य सभा में भी हाऊस कमेटी है । ... (व्यवधान)

श्री सभापति : इस वक्त सवाल मेम्बर्ज का नहीं है । यह तो सवाल कर रहे हैं कि जो इम्पलायीज हैं राज्य सभा के... **(व्यवधान)**

श्रीमती मोहसिना किदवई : इम्पलायीज के बारे में बात कर रही थी । बंसल साहब ने जो पूछा राज्य सभा और लोक सभा के जो इम्पलायीज हैं, उनके बारे में जो उन्होंने पूछा, उनका पूल भी अलग है और जनरल पूल से भी हम दे रहे हैं । लेकिन उसके बावजूद जरूरत पूरा नहीं हो पाती है । इस के लिए हमारी कोशिश है...

श्री सभापति : कुछ स्पेशल स्कीम बना रही हैं आप, ताकि उनको यह परेशानी न रहे, ताकि आपके यहां पर सर्विस अच्छी हो सके ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : तब जब हमें कन्स्ट्रक्शन के लिए ज्यादा पैसा मिलेगा फाईनांस मिनिस्ट्री हमारे ऊपर मेहरबान होगी तो हम ज्यादा से ज्यादा ....

श्री सभापति : राज्य सभा और लोक सभा के इम्पलोईज के लिए कुछ प्रायरिटी मिलेगी या फिर आप इधर-उधर कर देंगी ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : नहीं, जैसे बनेगे उसमें देखेंगे कि उनका कितना हिस्सा होता है ।

*362 *[The Questioner {Shri KV Thangkabatu) was absent for answer vide col..... 46 and 47---- infra.]*

•363 *[The questioners (Shri V. Gopalsamy and Shri Pasumpon Tha Kiruttinan) were absent For answer ride col. 47 and 48 infra.]*

भारतीय खाद्य निगम में वेतन संशोधन संबंधी मिश्र समिति की सिफारिश

***364. श्री अश्विनी कुमार :**
श्री लाल कृष्ण आडवाणी :†

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम में वेतन संशोधन संबंधी मिश्र समिति के प्रतिवेदन में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ख) स्वीकार कर ली गई सफारिशों और प्रत्येक सिफारिश पर पृथक-पृथक रूप से सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) रिपोर्ट फरवरी, 1989 में संसद के पुस्तकालय में रख दी गई थी ।

(ख) सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है ।

SHRI LAL K. ADVANI : Mr. Chairman, Sir, I am extremely disappointed with this answer because here the question relating to as many as nearly $2^{1/2}$ lakh employees who have been working in 68 different public sector undertaking and this Committee was appointed to recommend revision of pay scales and service conditions in respect of these *2 1/2* lakh employees. Though it was appointed way back in 86 April, asked to submit its report in four months, the Committee itself took some time, nearly 18 months and since. November 1988 this report has been lying with the Government of India. It is rightly said that the Committee's report has been placed in the Library but this was not intended to be placed in the Library only it was intended to be implemented. Why has it not been implemented, particularly when these employees have been looking forward to wage revision since 1973? Since 1973 there has been no change in their pay scales and service conditions. Why has it not been implemented ? After all 68 Public sector undertakings, including the prestigious ones like the Food Corporation of India about which I have specifically asked, UDC, the Delhi Transport Corporation, the NPCC, the HUDCO, the NTC,(National Textile Corporation) and so

†सभा में यह प्रश्न श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा पूछा गया ।